भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 5326

दिनांक 25/03/2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 पोर्टल

5326. श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री अरुण गोविलः

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन्नत राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) 2.0 पोर्टल के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत दर्ज संस्थागत पंजीकरणों तथा व्यक्तिगत भागीदारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में युवा संसद कार्यक्रम के विस्तार की क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त पहल के परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक भागीदारी में हुई किसी वृद्धि का आकलन किया है; और

(घ) क्या इसे और बड़े पैमाने पर विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): युवा संसद कार्यक्रम का विस्तार करने तथा विद्यार्थियों/नागरिकों की व्यापक प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने 11 सितंबर, 2024 को राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) वेब पोर्टल के एक उन्नत संस्करण की शुरूआत की है जिसे एनवाईपीएस 2.0 के नाम से जाना जाता है। केवल मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित पूर्व संस्करण के विपरीत, एनवाईपीएस 2.0 के तहत देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थान, समूह और नागरिक भी क्रमश: संस्थागत प्रतिभागिता, समूह द्वारा प्रतिभागिता और व्यक्तिगत प्रतिभागिता के माध्यम से भाग ले सकते हैं। यह देश में लिंग, जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, निवास स्थान आदि की परवाह किए बिना प्रतिभागिता हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एनवाईपीएस के दायरे को और विस्तृत करने के लिए, मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों और विभिन्न शिक्षा बोर्डों (सीबीएसई, सीआईएससीई) को भी लिखा है और साथ ही संसद टीवी पर समय-समय पर एक प्रचार वीडियो ट्यूटोरियल भी प्रसारित किया जाता है। एनवाईपीएस 2.0 की शुरूआत के बाद से, देश में कुल 4,594 संस्थानों ने संस्थागत भागीदारी के तहत पंजीकरण किया है और 44,403 लोगों ने व्यक्तिगत प्रतिभागिता के तहत भाग लिया है।

(ग) और (घ): मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

***